

हिन्दुस्तान

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट पर शुक्रवार को मिलेनियम सिटी के लोगों पर नजर रहेगी

छह लाख रुपये तक की आय पर कर में छूट मिले



गुरुग्राम | कार्यालय संवाददाता

मोदी सरकार शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में यह बजट पेश करेंगी तो मिलेनियम सिटी के उद्योग जगत और नौकरीपेशा लोगों की इस पर गहरी नजर रहेगी। इससे गृहणियों का बजट और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। नौकरीपेशा लोग छह लाख तक की आमदनी वालों को आयकर छूट में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा लोग जरूरी चीजों के सस्ती होने की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि कर कम हुए तो लोगों के पास नगदी बचेगी और जिंदगी आसान होगी। दरअसल मिलेनियम सिटी में काफी इंडस्ट्री हैं और वहां से दिल्ली-एनसीआर तक सरकारी-निजी दफ्तरों में काम करने वाले लोग यहां रहते हैं। इसके अलावा

तमाम उद्योगों में मजदूर काम करते हैं, जिन्हें सरकारी मदद की जरूरत होती है। ऐसे में रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी चीजों पर करों में कमी और आयकर स्लैब में छूट बढ़ने से इनकी जिंदगी आसान होती है। वहीं उद्योगों के लिए अच्छे फैसले से रोजगार और वेतन में बढ़ोतरी की गुंजाइश बढ़ती है। इससे नौकरीपेशा से लेकर गृहणी और उद्यमियों से लेकर बिल्डर तक हर कोई मोदी सरकार के इस बजट से आस लगाए हुए है। लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार का यह बजट सभी वर्गों को लाभ देने वाला होगा।

लोन पर लिए जाने वाले ब्याज में कमी की मांग : मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल के आखिर में पांच लाख रुपये तक की आमदनी को करमुक्त कर लोगों को राहत दी थी। नौकरीपेशा लोगों को इस बार के बजट में भी आयकर पर दी जाने वाली छूट में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उन्हें आस है कि सरकार पांच लाख रुपये सालाना से अधिक कमाने वालों को भी कर के भुगतान में राहत देगी। इसके अलावा लोग बैंक में निवेश और लोन पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों में भी बदलाव होने की आस लगाए हुए हैं। वहीं नौकरी करने वालों को कर मुक्त ग्रेज्युटी की



शहर के कारोबारियों और दुकानदारों को भी आम बजट से रियायत की उम्मीद है। • फाइल फोटो

सीमा पिछले बजट से अधिक बढ़ने की भी उम्मीद है।

स्टॉप शुल्क खत्म हो : रियल एस्टेट को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इससे जुड़े लोगों को भी मोदी सरकार के दूसरे बजट से कई उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को आस है कि सरकार इस बजट में स्टॉप शुल्क को समाप्त कर

देगी। बिल्डरों के मुताबिक स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क खरीदारों के लिए बोझ बने हुए हैं, जो खरीदारों को बाजार से दूर रख रहे हैं।

शिक्षा सस्ती हो : नए बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी योजनाएं आने की उम्मीद है। लोगों का कहना है कि शिक्षा सस्ती की जाए।

जीएसटी स्लैब पर दुकानदारों की नजर

मिलेनियम सिटी के उद्यमी नए बजट में राहत की बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। उद्यमियों की सबसे पहली उम्मीद उत्पाद के निर्यात पर मिलने वाले इंटेंसिव में बढ़ोतरी होना है। इसके अलावा उन्हें उद्योग शुरू करने के लिए बैंक से मिलने वाले लोन की दरों में भी कमी आने की आस है। उद्यमियों का कहना है कि सरकार को इस बजट में जीएसटी स्लैब में भी बदलाव करना चाहिए। मौजूद जीएसटी स्लैब से केवल बड़े उद्यमियों को फायदा हो रहा है। यदि जीएम स्लैब एक हो जाता है तो छोटे उद्यमी भी इसका लाभ ले सकेंगे। वहीं जीएसटी रिफंड पॉलिसी में भी बदलाव करना चाहिए।

रोजमर्रा के घरेलू सामान की कीमत घटे

मोदी सरकार का आम बजट महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इससे शहर की गृहणियों को उम्मीद है कि वे गृहणियों की परेशानियों को अधिक समझ सकेंगी और बजट में इसकी झलक दिखेगी।

गृहणियों का कहना है कि वित्त मंत्री घरेलू सामानों की महंगाई कम करने का प्रयास करेंगी। महिलाओं का कहना है कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामानों, बिजली, दाल, चावल, चीनी सस्ते होने चाहिए।



उत्पादों के निर्यात पर अभी करीब 2 फीसदी का प्रोत्साहन मिलता है। यदि सरकार इस प्रोत्साहन में बढ़ोतरी करे तो निर्यात को बढ़ावा जा सकता है। - मुनेश त्यागी, उद्यमी, जेडीएम ओवरसीस प्रांति



जीएसटी का एक स्लैब हो जिससे हर वर्ग के उद्यमी को लाभ मिले। बिजनेस लोन की दरें भी कम हों, जिससे नए उद्योग शुरू कर सकें। - प्रवीण यादव उद्यमी, गुरुग्राम



स्टॉप और पंजीकरण शुल्क को खत्म किया जाए। यह खरीदारों को रियल एस्टेट क्षेत्र से दूर कर रहा है। इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। - आशीष सरिन सीईओ, अल्का कॉर्प



रियल एस्टेट सेक्टर को लंबे समय से उद्योग का दर्जा देने की मांग की जा रही है। उम्मीद है इस बजट में सरकार रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा देगी। - आमिर इरैन, आरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर



आयकर छूट में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी और नौकरीपेशा को दी जाने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार राहत दे। - संजु यादव, नर्सिंग ऑफिसर, एम्स



महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं, उम्मीद है वह गृहणियों का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगी। रोजमर्रा के घरेलू सामानों की कीमतें कम होने की उम्मीद है। - राज, गृहणी



सरकारी स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य का काफी बुरा हाल है। उम्मीद है इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में ही सुधार के लिए सरकार कुछ नया पेश करेगी। - अकिंत वोहरा, अधिकारी